

<><><><><><><><>

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया।
- 'नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवनशैली अपनानी चाहिए।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से द्वीप समूह में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन। भारत 13 स्वर्ण सहित उनतालीस पदकों के साथ चौथे स्थान पर।

<><><><><><><><>

लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, उन्नीस सौ छप्पन में और संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या तैंतीस से बढ़ाकर सैंतीस करना है। यह संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त है। इस वर्ष मई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या तैंतीस से बढ़ाकर सैंतीस करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था।

<><><><><><><><>

राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक-2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य एम एस एम ई क्षेत्र में भुगतान में देरी की समस्या दूर करना और विवाद समाधान की प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके तहत मध्यस्थता विफल होने पर तीस दिनों के भीतर मामला भेजने और नब्बे दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान किया गया है। छह महीने से अधिक समय तक लंबित मामलों में आपूर्तिकर्ता को देय राशि का कम से कम पचास प्रतिशत भुगतान करना होगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि सरकार एम एस एम ई क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

<><><><><><><><>

अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने उद्योगों और संबंधित प्रतिष्ठानों से सहमति प्रमाणपत्र-सी टी ओ के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने को कहा है। सभी उद्योग, संस्थान, स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, स्थानीय निकाय और अन्य संबंधित हितधारक यू सी एम एस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। समिति ने कहा है कि पर्यावरणीय नियमों के अनुरूप आवेदनों पर विचार किया जाएगा। जिन प्रतिष्ठानों के पास वैध सहमति प्रमाणपत्र नहीं है, वे जल्द अपना आवेदन जमा करें। अधिक जानकारी और तकनीकी सहायता के लिए प्रदूषण नियंत्रण समिति से संपर्क किया जा सकता है।

<><><><><><><><>

अंडमान निकोबार प्रादेशिक असंगठित मजदूर एवं कर्मचारी कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रंगलाल हलदर मुख्य अतिथि और दक्षिण अंडमान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जॉन रॉबर्ट विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर असंगठित क्षेत्र के 25 उत्कृष्ट श्रमिकों को उनके योगदान के लिए श्रम रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

<><><><><><><><>

अंडमान निकोबार पैरा वेटनरी संघ के अध्यक्ष आर पी यादव ने मध्योत्तर अंडमान का दौरा किया। अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने पैरा वेटनरी कर्मचारियों से संवाद कर उनकी सेवा संबंधी समस्याओं एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उन्होंने पैरा वेटनरी कर्मचारियों के साथ मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। अध्यक्ष ने मायाबंदर के जोनल अधिकारी से मुलाकात कर वेटनरी कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने पर भी विचार विमर्श किया गया।

